फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 77 संख्याः 11 प्रभात जयपुर, मंगलवार 11 अगस्त, 2026 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

ARBiT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

epaper.rashtradoot.com

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

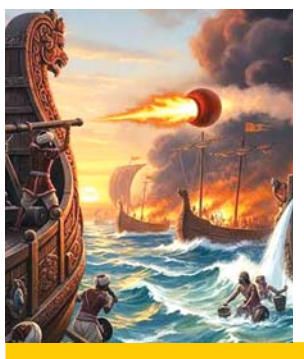

From Rig Veda To Indian Navy

Maurya, Satavahana, Chola, Vijayanagara, Kalinga, Maratha and Mughal empires had powerful navies, it was the Cholas who did very well in foreign trade

An Iron Age Hoard

The researchers are fascinated by the bronze boar's head in the hoard. Experts think it is "similar to a modern-day flagpole"

संसद के मानसून सत्र में मात्र 3 दिन बचे हैं

गतिरोध खत्म होने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है

- संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि विपक्ष अमित शाह के बयान की मांग कर रहा है और गृह मंत्री अमित शाह सदन में आकर बात करने को तैयार हैं, बशर्ते विपक्षी दल उनका पक्ष सुनें।
- लेकिन, राहुल गांधी ने तीन शर्तें रखी हैं, जिन पर वे झुकने को तैयार नहीं हैं। पहली शर्त है, छात्रों पर पैलैट गन चलाने की अनुमति किसने दी, दूसरी शर्त, अखिलेश यादव की मांग पर है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का जिम्मेवार कौन है, तीसरी शर्त यह कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री 20 जुलाई की घटना के लिए देश से माफी मांगें।
- सरकार की कोशिश है कि वह अपने दो महत्वपूर्ण बिल, परिसीमन बिल और एफसीआरए पारित करा ले। सरकार का जोर परिसीमन बिल पर है और इसके लिए वह एफसीआरए के कुछ प्रावधानों को हल्का कर सकती है ताकि द्रमुक जैसे दल समर्थन दे दें।

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 अगस्त। संसद का मानसून सत्र 16 दिनों से अवरूद्ध है और अब सत्र समाप्त होने में सिर्फ तीन दिन बाकी हैं। ऐसे में फिलहाल किसी बड़े समाधान की संभावना नज़र नहीं आ रही है।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि अमित शाह सदन में आने और बोलने के लिए तैयार हैं, बशर्ते विपक्ष उनकी बात सुने और उन्हें बोलने दे।

एफसीआरए और परिसीमन विधेयक अब भी अनिश्चितता के घेरे में हैं। भाजपा का दावा है कि उसके पास परिसीमन विधेयक पारित कराने के लिए पर्याप्त संख्या में सांसदों का समर्थन है।

इस बीच, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला एक समझौता कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसके तहत सरकार एफसीआरए विधेयक में बदलाव कर सकती है या उसे वापस ले सकती है, ताकि विपक्ष, खासकर डीएमके, को संतुष्ट किया जा सके और परिसीमन विधेयक पर उसका समर्थन हासिल किया जा सके।

तमिलनाडु के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, "डीएमके के लिए परिसीमन विधेयक का समर्थन करना आत्मघाती होगा।"

राहुल गांधी ने सदन चलाने के लिए तीन ऐसी शर्तें रखी हैं, जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता।

पहली, अमित शाह को सदन में आकर यह बताना होगा कि क्या उन्होंने छात्रों पर पैलैट चलाने की अनुमति दी थी। अगर नहीं, तो फिर इसकी अनुमति किसने दी?

दूसरी, अखिलेश यादव के आग्रह पर कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए कि राम मंदिर में "चढ़ावे की चोरी" के लिए कौन जिम्मेदार है और इसके पीछे कौन-कौन लोग हैं

तीसरी, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों को राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए कि पुलिस और सरकार ने छात्रों के साथ किस तरह का व्यवहार किया।

प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों के बार-बार सदन में आने की मांग के बावजूद सदन से दूर रहने के कारण विपक्ष ने यह नैरेटिव स्थापित कर दिया है कि दोनों अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करने से बच रहे हैं और सदन में होने वाली नारेबाजी तथा आलोचना का सामना करने को तैयार नहीं हैं।

फिलहाल संसद में भारी गतिरोध में है।

जब तक अमित शाह सदन में आकर इस बात की जानकारी नहीं देते कि 20 जुलाई को वास्तव में क्या हुआ, इसकी पूरी जानकारी नहीं देते, तब तक सदन के सुचारू रूप से चलने की संभावना नहीं है।

और जब तक सदन की कार्यवाही नहीं चलती, तब तक परिसीमन संबंधी संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं किया जा सकता।

निकाय प्रमुखों व जिला प्रमुखों के आरक्षण की लॉटरी 13 को

जयपुर, 10 अगस्त। राजस्थान में आगामी नगरीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव से पहले प्रमुख पदों के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। प्रदेश के नगरीय निकायों में मेयर, सभापति और चेयरमैन के पदों के आरक्षण की लॉटरी 13 अगस्त को निकाली जाएगी। इसी दिन प्रदेश के 41 जिला प्रमुखों के पदों के आरक्षण की लॉटरी भी होगी।

लॉटरी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक दलों को पत्र भेजकर आमंत्रित किया गया है।

- लॉटरी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए राज्य सरकार ने प्रमुख राजनीतिक दलों को आमंत्रण भेजा।

स्वायत्त शासन निदेशालय के निदेशक की ओर से जारी आदेश के अनुसार, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के प्रमुख पदों के आरक्षण की लॉटरी 13 अगस्त को सुबह 10:30 बजे स्वायत्त शासन निदेशालय में निकाली जाएगी।

इस प्रक्रिया के जरिए यह तय होगा कि किस नगरीय निकाय में मेयर, सभापति अथवा चेयरमैन का पद किस वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा।

ईरान की कूटनीति में कट्टरपंथियों का दबदबा बढ़ रहा है

कट्टरपंथी गुट ने अमेरिका से अरबों डॉलर का युद्ध हर्जाना मांगा है, जिसे मानना अमेरिका के लिए संभव नहीं लग रहा

- ईरान ने मांग की है कि अमेरिका होर्मुज़ और हिंद महासागर में ईरान के खिलाफ की गई तमाम घेराबंदी हटा दिया जाए। ईरान का फ्रीज़ किया हुआ फंड लौटाया जाए और अमेरिका अरबों डॉलर का हर्जाना भी दे।
- ईरान की तरफ से यह मांग ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के एक पूर्व कमांडर ने रखी है, जिसे मोज़तबा खामनेई ने कूटनीति वार्ताओं को हैंडल करने के लिए नियुक्त किया है।
- ट्रंप के दोनों लक्ष्य, पहला होर्मुज़ स्ट्रेट को खोलना व दूसरा ईरान न्यूक्लियर कार्यक्रम पर नियंत्रण करना, न केवल दूर होते लग रहे हैं, बल्कि मिडिल ईस्ट से अमेरिका का दबदबा भी कम होता लग रहा है।

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 अगस्त। ईरान की घरेलू राजनीतिक स्थिति एक नए दौर की ओर बढ़ती दिख रही है और कट्टरपंथी ताकतें कूटनीतिक पहल अपने हाथ में ले रही हैं। ऐसे में किसी समझौते की संभावना लगातार कम होती जा रही है।

ईरान अब अपनी मांगों को बहुत बढ़ा रहा है, जिन्हें मानना अमेरिकियों के लिए लगभग असंभव है। ईरान की नई मांगें ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के एक पूर्व कमांडर की ओर से आई हैं, जिन्होंने एक अधिक नरम रुख वाले अधिकारी की जगह ली हैं। नए नेता की नियुक्ति कथित तौर पर मोजतबा खामेनेई ने अपने छिपने के स्थान से की है।

ईरान मांग कर रहा है कि हिंद महासागर जाने वाले होर्मुज़ जलडमरूमध्य के रास्ते पर ईरानी जहाजों, खासकर ईरान से तेल ले जाने वाले जहाजों पर लगी अमेरिकी नाकाबंदी को तुरंत हटाया जाए। असल में होर्मुज़ से निकलने वाले सभी ईरानी जहाजों पर अमेरिकी नाकाबंदी ईरान की अर्थव्यवस्था का गला घोंट रही है।

ईरान यह भी मांग कर रहा है कि उसके फ्रोज़न फंड को तुरंत जारी किया जाए, देश पर लगाए गए प्रतिबंध हटाए जाएं और युद्ध के कारण अमेरिका से मुआवज़ा देने की आगे की प्रतिबद्धता ली जाए।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'जर्जर हो रहा गुंबद हजारों की जान के लिए खतरा है'

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार एवं प्रशासन को घेरा और जवाब मांगा, हजारों लोगों की सुरक्षा को क्यों अनदेखा किया जा रहा है

- अदालत ने अगली सुनवाई पर राज्य सरकार के मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव, वित्त विभाग के प्रमुख सचिव, डीजीपी पुलिस और आरएसआरडीसी के मुख्य निदेशक को अदालत में जवाब सहित प्रस्तुत रहने को कहा है।
- आईआईटी जोधपुर और बॉम्बे की दो रिपोर्ट यह स्पष्ट दर्शाती है कि हाईकोर्ट की बिल्डिंग पर बने गुम्बद की हालत जर्जर है, वह कभी भी गिर सकता है।

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 10अगस्त। जोधपुर स्थित राजस्थान हाईकोर्ट की प्रधान पीठ की बिल्डिंग पर बने गुम्बद के ढांचे में संरचनात्मक दोष पाए जाने के मुद्दे पर सुनवाई हुई। न्यायधीश पुष्पेन्द्र भाटी और न्यायधीश प्रवीन भटनागर ने मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए, इस मामले को जनहित याचिका के रूप में सुनने का फैसला लिया। अदालत ने मामले में राज्य सरकार, सार्वजनिक निर्माण विभाग, कानून विभाग, केन्द्र सरकार, राजस्थान पुलिस और राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड और हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को पक्षकार बनाकर नोटिस जारी किए। अदालत ने पक्षकारों को शपथ पत्र पर जवाब प्रस्तुत करने को कहा है कि हाईकोर्ट की इमारत की "सेफ्टी ऑडिट", संरचनात्मक ढांचे के सुरक्षात्मक मापदंड और भार सहने की क्षमता पर जवाब पेश करें। अदालत ने यह भी कहा है कि पक्षकार बताएं कि ढांचे में त्रुटियां रह जाने के बाद भी प्रशासन सोता क्यों रहा और क्यों इस गंभीर मुद्दे से हजारों लोगों की जान हर रोज जोखिम में डाली जा रही है। अदालत ने पूछा है कि प्रशासन अब गुम्बद के ढांचे में सुधार करने व मजबूती देने के लिए क्या करेगा। अदालत ने कहा है कि जब तक प्रशासन अपना जवाब प्रस्तुत करता है और सुनवाई आगे बढ़ती है, उससे पूर्व पक्षकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि अस्थाई तौर पर ऐसे निवारक कदम उठाए जाएं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि गुम्बद अकस्मात नीचे न गिर जाए और लोग

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

उच्चतम न्यायालय की समिति ने उदयपुर में अरावली पर जन संवाद किया

उदयपुर, 10 अगस्त (निसं)। अरावली पर्वत श्रृंखला के संरक्षण एवं सतत विकास को लेकर सोमवार को जिला परिषद सभागार में व्यापक जन संवाद आयोजित हुआ। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशन में भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई) की महानिदेशक कंचन देवी की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने जनप्रतिनिधियों, खनन पट्टा धारकों, स्वयंसेवी संगठनों, पर्यावरणविदों, पशुपालकों एवं विभिन्न हितधारकों से अरावली संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से परामर्श किया। सवेदनशील मुद्दे पर आयोजित संवाद मात्र दो घंटे में समाप्त किये जाने पर कमेटी के सामने लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा।

- मात्र दो घंटे में जन संवाद पूरा किये जाने पर लोगों ने नाराज़गी जताई।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एक बार फिर वरुण गांधी के कांग्रेस में जाने की चर्चा तेज हुई

इलाहाबाद में राहुल के "छात्रों की गूंज" कार्यक्रम में ऐसे पोस्टर देखे गए, जिनमें राहुल, वरुण और प्रियंका गांधी को दिखाया गया था

- पता चला है कि ये पोस्टर इलाहाबाद हाई कोर्ट के दो वकीलों ने लगाए थे, जिन्हें बाद में हटा दिया गया था।
- गांधी परिवार के इन दोनों गुटों के पुनः एक होने की चर्चा अक्सर होती रहती है। वर्ष 2023 में केदारनाथ में राहुल और वरुण की अचानक मुलाकात हुई, दोनों गर्म जोशी से मिले, तब भी वरुण के कांग्रेस में आने की अटकलों को बढ़ावा मिला था।
- पीलीभीत से भाजपा के सांसद रहे वरुण अक्सर विभिन्न मंचों से भाजपा की आलोचना करते रहे हैं।

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 अगस्त। ऐसी अटकलें फिर तेज हो गई हैं कि फ़िरोज़ वरुण गांधी कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। इन अटकलों को प्रयागराज में राहुल गांधी के हालिया "छात्रों की गूंज" संवाद के दौरान लगाए गए पोस्टरों से और बल मिला। केपी ग्राउंड के मुख्य द्वार के बाहर लगाए गए पोस्टरों में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और वरुण गांधी को एक साथ दिखाया गया था। एक पोस्टर में राहुल और वरुण को हाथ मिलाते हुए भी दिखाया गया था। पोस्टर पर संदेश लिखा था "अगर 'भारत को एकजुट' करने का संदेश देना है, तो शुरुआत अपने परिवार को एकजुट करने से करें।" इसके साथ नारा था- "साथ आइए, नए भारत की शुरुआत करें।"

ये पोस्टर इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं -संतोष सिंह और रवि सोनकर (गोलू) ने लगाए थे। बताया जाता है कि अज्ञात लोगों ने कुछ ही समय बाद इन्हें फाड़ दिया।

इन तस्वीरों ने लंबे समय से चली आ रही उन चर्चाओं को फिर हवा दे दी है कि राजनीतिक विभाजन के बावजूद गांधी परिवार के दोनों गुटों के बीच पुनर्मिलन हो सकता है। पीलीभीत से तीन बार भाजपा सांसद रह चुके वरुण को 2024 में लोकसभा चुनाव का टिकट नहीं दिया गया था। वे सार्वजनिक मंचों पर कई बार अपनी पार्टी भाजपा की नीतियों की आलोचना भी कर चुके हैं। इसके चलते कम से कम 2016-18 से ही उनके कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें लगती रही हैं।

2021 में इन अटकलों को तब और बल मिला, जब वरुण और उनकी मां मेनका गांधी को भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर कर दिया गया। इसके बाद नवंबर 2023 में केदारनाथ में राहुल गांधी से उनकी अचानक हुई मुलाकात और फिर 2024 में टिकट से वंचित किए जाने के बाद भी कांग्रेस में उनके जाने की चर्चाएं तेज हुईं। 2026 की शुरुआत में मीडिया रिपोर्टों में प्रियंका गांधी के साथ उनके संपर्क या मुलाकात के दावे भी सामने आए, हालांकि दोनों पक्षों ने किसी औपचारिक बातचीत की पुष्टि नहीं की है।

पिछले पांच वर्षों में वरुण और उनके चचेरे भाई-बहनों के बीच सार्वजनिक रूप से सुपुष्ट की गई मुलाकातें सीमित रही हैं। सबसे उल्लेखनीय घटना नवंबर 2023 में केदारनाथ मंदिर के बाहर राहुल गांधी के साथ उनकी संक्षिप्त और गर्मजोशी भरी अचानक हुई मुलाकात थी, जिसमें दोनों ने एक-दूसरे का

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

शरद पवार की पार्टी परिसीमन बिल का समर्थन करेगी?

- एनसीपी का एक प्रतिनिधिमंडल आज सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मिला और इसके बाद से यह सवाल पूछा जा रहा है।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 अगस्त। शरद पवार की एनसीपी के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने, वरिष्ठ नेता सुप्रिया सुले के नेतृत्व में, सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। यह मुलाकात ऐसे समय हुई है, जब अटकलें लगाई जा रही

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ट्रंप ईरान वॉर से सम्मानजनक तरीके से निकलना चाहते हैं

उनकी कोशिश है कि होर्मुज़ स्ट्रेट खुल जाए ताकि वे अमेरिका के मिड टर्म चुनाव में इसे बतौर उपलब्धि पेश कर सकें

- वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि ट्रंप ने निजी तौर पर अपने वरिष्ठ सलाहकारों से कहा है कि अगर तेहरान होर्मुज़ स्ट्रेट खोल देता है तो वे ईरान पर नए न्यूक्लियर एग्रीमेंट के लिए भी दबाव नहीं डालेंगे और ईरान वॉर से हट जाएंगे।
- इससे स्पष्ट है कि वॉशिंगटन के युद्ध संबंधी लक्ष्यों में भारी बदलाव आया है। अब वह न्यूक्लियर समझौते पर दबाव नहीं डाल रहा है और मौजूदा सैन्य टकराव को ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम पर चले आ रहे दीर्घकालीन विवाद से अलग रखने को भी तैयार है।
- वॉशिंगटन के लिए राजनीतिक स्थिति भी आर्थिक हालात जितनी ही महत्वपूर्ण है, ट्रंप नहीं चाहते कि ईरान के साथ उनका संघर्ष एक अंतहीन सैन्य टकराव में बदल जाए। अगर युद्ध लंबा चला तो उनका प्रभाव कम हो जाएगा और अगर उन्होंने तेहरान के साथ समझौता कर लिया तो ईरान पर जीत दर्ज करने का उनका दावा हल्का पड़ जाएगा।

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 अगस्त। ईरान युद्ध से सम्मानजनक तरीके से बाहर निकलने की राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की कोशिशों को एक बड़ी मुश्किल का सामना करना पड रहा है। तेहरान ने बातचीत में अपना रुख कड़ा कर लिया है और युद्ध से हुए नुकसान के लिए अरबों डॉलर के मुआवजे और अमेरिकी सैनिकों की पूरी तरह वापसी की मांग की है। इन शर्तों के कारण वॉशिंगटन के लिए अमेरिकी मध्यावधि चुनावों से पहले युद्ध में जीत का ऐलान करना और संघर्ष को खत्म करना मुश्किल हो सकता है।

ट्रंप स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को फिर से खोलने को सफलता के सबसे बड़े सबूत के तौर पर पेश करने की तैयारी कर रहे थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रपति ने निजी तौर पर अपने वरिष्ठ सहयोगियों से कहा था कि अगर तेहरान रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण इस जलमार्ग को पूरी तरह से फिर से खोल देता है, तो वह ईरान के साथ नए परमाणु समझौते के बिना भी युद्ध से पीछे हटने के लिए तैयार हो सकते हैं।

यह वॉशिंगटन के युद्ध के उद्देश्यों में एक संभावित बड़ा बदलाव हो सकता था। संघर्ष खत्म करने से पहले व्यापक परमाणु समझौते पर जोर देने के बजाय, ट्रंप प्रशासन ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद से तत्काल सैन्य टकराव को अलग करने के लिए अधिक इच्छुक दिख रहा था।

लेकिन तेहरान की नई मांगों ने उस हिसाब- किताब को मुश्किल बना दिया है।

रिपोर्टों के अनुसार, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को फिर से खोलने को एक बड़े समझौते से जोड़ दिया है, जिसमें युद्ध से हुए नुकसान के लिए अरबों डॉलर का मुआवजा, अमेरिकी सैनिकों की पूरी वापसी, अमेरिकी सैन्य दबाव को खत्म करना और प्रतिबंधों में राहत शामिल हैं। इन मांगों से जलमार्ग को फिर से खोलना महज विश्वास बढ़ाने वाला कदम नहीं रह जाता, बल्कि अमेरिका और ईरान के भविष्य के संबंधों को लेकर एक बड़े समझौते का हिस्सा बन जाता है।

इससे ट्रंप के सामने एक मुश्किल विकल्प खड़ा हो गया है। ईरान की बड़ी मांगों को मानने पर उन्हें इस आलोचना का सामना करना पड सकता है कि अमेरिका ने संघर्ष खत्म करने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई। वहीं, मांगों

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'जंतर मंतर पर न गोली चली न ऐसा कोई आदेश दिया गया'

नई दिल्ली, 10 अगस्त। केन्द्रीय मंत्री और राज्य सभा में सत्ता पक्ष के नेता जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को आड़े लेते हुए उन्हें सदन में चर्चा के लिए चुनौती दी। जे पी नड्डा ने कहा कि सरकार सदन में चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को उचित जवाब दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि विपक्ष को गलत जानकारी नहीं फैलानी चाहिए, क्योंकि जंतर-मंतर पर न तो कोई गोली चलाई गई थी और न ही वहां गोली चलाने का कोई आदेश दिया गया था।

सोमवार को अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत में केन्द्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी संसद में और जनता के बीच अपनी बात लगातार बदलते रहते हैं। उनका उद्देश्य बातचीत करना नहीं, बल्कि अराजकता फैलाना है।

सत्र की शुरुआत में उन्होंने नीट पर चर्चा की मांग की। जब हम उस पर चर्चा के लिए तैयार हुए, तो उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट का मुद्दा उठा दिया।